पूर्ण बेंच

माननीय एस. एस. संधावालिया, सी.जे.,

एम.आर.शर्मा और जी.सी. मित्तल, जे.जे.

के समक्ष

रति राम और एक अन्य, अपीलकर्ता

बनाम

शिव चरण और अन्य, *उत्तरदाता*

नियमित द्वितीय अपील सं. 1969 का 140

23 जुलाई, 1981

रिवाज-रोहतक जिला- रोहतक तहसील में एक *पुत्रहीन* मालिक की शक्तियां- *ऐसा मालिक - क्या सेवाओं के बदले घनिष्ठ संबंध के पक्ष में पैतृक भूमि का वसीयतनामा करने के लिए सक्षम है।*

और रूप 'रोहतक तहसील में एक बेबेटे मालिक की अपनी पैतृक संपत्ति को विचार के लिए अलग करने की शक्ति को तब भी मान्यता दी जाती है, जब बिक्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते कि अलगाव अनैतिक उद्देश्य के लिए न हो। अलगाव के लिए विचार या तो नकद में या किसी प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात, सेवाओं के रूप में और चूंकि हस्तांतरण के बीच कोई अंतर नहीं है। *Inter vivos* और एक हस्तांतरण जो हस्तांतरणकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होता है, यह अनुमान लगाना उचित होगा कि सेवाओं के बदले घनिष्ठ संबंध

के पक्ष में पैतृक भूमि के वसीयतनामे को प्रथागत कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। (पैरा 10)।

माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा द्वारा 5 मार्च, 1980 *को मामले में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए एक पूर्ण पीठ को मामला भेजा गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एसएस संधावालिया, माननीय न्यायमूर्ति एमआर शर्मा और माननीय न्यायमूर्ति जीसी मित्तल की पूर्ण पीठ ने 23 जुलाई,* 1981 को मामले का अंतिम निर्णय लिया।

रोहतक के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री बी एस यादव के न्यायालय के दिनांक 30 अक्तूबर, 1968 के आदेश से नियमित द्वितीय अपील, जिसमें 23 नवम्बर, 1966 *को रोहतक के प्रथम श्रेणी के उप-न्यायाधीश श्री वी. बी. बंसल द्वारा* प्रतिवादियों सं 20066 के विरुद्ध वाद दायर किए जाने *की पुष्टि की गई थी। विवादित भूमि के संबंध में* 1 *और 2 लेकिन विवादित घरों के बारे में इसे खारिज करना और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के खिलाफ मुकदमा भी खारिज करना, उनके खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया है और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।*

अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट यू.डी.गौड़ *ने कहा।*

एल. सरीन, *वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता आर. एल. सरीन।*

निर्णय

एम. आर. शर्मा, जे.

(एक) क्या प्रथागत कानून द्वारा शासित और रोहतक तहसील

से संबंधित एक पुत्रहीन गौड़ ब्राह्मण, सेवाओं के बदले घनिष्ठ संबंध के पक्ष में अपनी संपत्ति का वसीयत करने में सक्षम है या नहीं, यह एक छोटा सा सवाल है जिसे हमें इस मामले में तय करने के लिए बुलाया गया है।

(दो) जिन तथ्यों से यह विवाद उत्पन्न हुआ है, उन्हें ठीक से समझने के लिए, निम्नलिखित वंशावली तालिका पर एक नज़र डालना उपयोगी होगा -

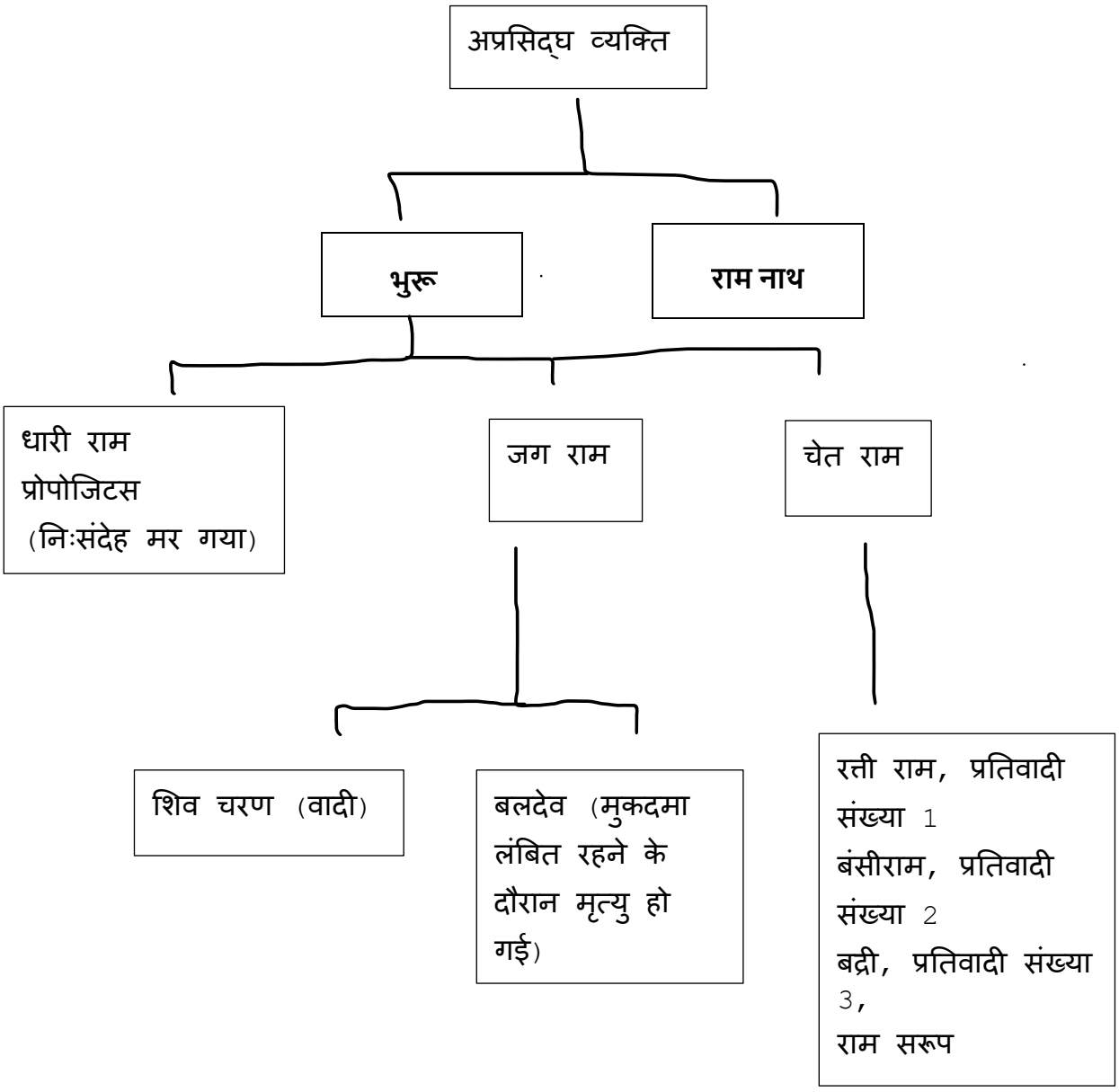

(तीन) चेत राम को राम नाथ ने बेटे के रूप में गोद लिया था। धारी राम मृतक के पास 1/ 66 कनाल 5 मरला की भूमि में चौथा हिस्सा और वाद में निर्दिष्ट दो घरों में 1/4 हिस्सा। 6 मई, 1964 को उन्होंने 6 मई, 1964 (प्रदर्शनी डीडब्ल्यू 1/1) की वसीयत को निष्पादित किया, जिसमें उपरोक्त संपत्ति में अपना हिस्सा प्रतिवादी-अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 रति राम और बंसी राम के पक्ष में वसीयत किया गया था। धारी राम का निधन 25 अप्रैल, 1965 को हुआ था। वादी-प्रतिवादी नंबर 1 शिव चरण ने इस आशय की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि पक्षकार प्रथागत कानून द्वारा शासित गौर ब्राह्मण थे और धारी राम प्रस्तावक को अपनी संपत्ति का वसीयत नामा करने से रोक दिया गया था, जो रति राम और बंसी राम के पक्ष में उनके पैतृक था। रति राम और बंसी राम प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने वाद में उठाई गई याचिकाओं का विरोध किया और जोर देकर कहा कि विवाद में वसीयत वैध थी क्योंकि यह सेवाओं के बदले में बनाई गई थी।

(चार) विद्वान ट्रायल जज ने मामले में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया

एक. क्या मुकदमे में संपत्ति पैतृक है या *वादी के लायक है*? ओ.पी.पी.

दो. क्या पार्टियों को प्रथा द्वारा अलगाव के मामलों में शासित किया जाता है, यदि हां, तो वह रिवाज क्या है? ओ.पी.पी.

तीन. यदि मुद्दा संख्या 1 और 2 वादी के पक्ष में साबित होते हैं, तो क्या वसीयत अलगाव के बराबर है? ओ.पी.पी.

चार. मदद।

(पाँच) मुद्दा संख्या 1 के तहत, यह माना गया था कि विवाद में भूमि पैतृक थी, लेकिन घर की संपत्ति पैतृक साबित नहीं हुई थी। मुद्दा संख्या 2 के तहत यह माना गया था कि पार्टियां प्रथा द्वारा शासित थीं, जिसके तहत धारी राम मृतक अपनी पैतृक संपत्ति का वसीयतनामा नहीं कर सकता था। मुद्दा संख्या 3 के तहत, यह माना गया था कि विल द्वारा स्वभाव एक अलगाव के बराबर था। इन निष्कर्षों पर, ट्रायल जज ने शिव चरण प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे को विवाद में भूमि की सीमा तक डिक्री की और घर की संपत्ति में धारी राम मृतक के हिस्से को खारिज कर दिया , रति राम और बंसी राम अपील में चले गए, जिसे रोहतक के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलीय अदालत ने विवाद में भूमि की पैतृक प्रकृति के बारे में निष्कर्ष की पुष्टि की और माना कि पार्टियां प्रथा द्वारा शासित थीं। इस मुद्दे पर कि क्या रति राम और बंसी राम ने प्रस्तावकर्ता को सेवाएं प्रदान की थीं या नहीं, यह निम्नानुसार था -

> "मैं यहां उल्लेख कर सकता हूं कि फाइल पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि अपीलकर्ताओं ने धारी को उसके जीवनकाल के दौरान सेवाएं प्रदान कीं और उसकी मृत्यु समारोह भी किए। धारी के भाई जग राम गांव दुबलधन माजरा में रहते थे, जहां उनकी शादी हुई थी। यह तथ्य वादी के साक्ष्य और प्रतिवादी के साक्ष्य से स्पष्ट है और यह मेरे सामने विवादित नहीं था। धारी के पास केवल दो किल्ला जमीन थी और कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि इतना क्षेत्र एक व्यक्ति की आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है। धारी अविवाहित था और जैसा कि पीडब्ल्यू

8 बंसी के बयान से स्पष्ट है, वह अपीलकर्ताओं के साथ रहता था और अपीलकर्ता उसे भोजन और कपड़े देते थे। उन्होंने आगे कहा है कि अपीलकर्ता धारी को सेवा प्रदान करते थे। इसी आशय के लिए डीडब्ल्यू 2 श्री राम, डीडब्ल्यू 5 पहलाद सिंह, डीडब्ल्यू 6 लछमन दास और डीडब्ल्यू 7 सुभा चंद के बयान हैं। प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील कोई तर्क नहीं दे पाए हैं कि इन गवाहों के बयानों पर विश्वास क्यों नहीं किया जाना चाहिए। वादी-प्रतिवादी नंबर 1 शिवचरण ने स्वीकार किया है कि उसके पिता गांव माजरा में रहते थे और उन्होंने अपनी शिक्षा भी वहीं प्राप्त की थी। इसलिए, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने धारी की सेवा की।

इस निष्कर्ष के बावजूद, यह रति राम और बंसी राम अपीलकर्ताओं के लिए इस आधार पर अनुकूल नहीं था कि एक पुत्रहीन मालिक के लिए वसीयत बनाकर अपनी पैतृक भूमि का निपटान करना खुला नहीं था।

(छः) प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने एक दूसरी अपील दायर की जो 8 मई, 1980 को मेरे सामने अंतिम सुनवाई के लिए आई। मेरे सामने, यह तर्क दिया गया था कि रोहतक तहसील के रिवाज-ए-एएम के तहत एक बेटाहीन मालिक अपनी जमीन को अलग कर सकता है, भले ही बिक्री की कोई आवश्यकता न हो, बशर्ते कि यह अनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया हो और ऐसे मालिक के खिलाफ सेवाओं के लिए अपनी जमीन का उपहार देने के लिए कोई प्रतिबंध न हो। इस आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि वसीयतनामा के स्वभाव के बारे में एक पुत्रहीन मालिक की शक्तियों पर लगाया गया प्रतिबंध अनुचित था। इस बिंदु पर मैंने पहले (*भीम* सिंह बनाम माही पट *और अन्य) (1) में अपीलकर्ता के पक्ष में एक दृष्टिकोण अपनाया था, लेकिन उस*

दृष्टिकोण को 'एलपी बेंच ने महिपत और अन्य *बनाम* भीम सिंह और अन्य *(2) में उलट दिया था।*

(सात) अपीलकर्ताओं के वकील श्री यूडी गौड़ ने प्रस्तुत किया कि एल.पी. बेंच द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को "माली बनाम रणबीर सिंह और अन्य (3) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर टिकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चूंकि इस निर्णय का मेरे समक्ष उल्लेख नहीं किया गया था जब मैंने दूसरी अपील का निर्णय लिया था या जब मामला उसके समक्ष आया था, तब एलपी पीठ के समक्ष, मैंने सिफारिश की थी कि इस मामले का निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। मेरे भगवान, मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को एक पूर्ण पीठ द्वारा तय करने का आदेश दिया। इस तरह यह मामला हमारे सामने आया है।

(आठ) जहां तक रोहतक तहसील में प्रथागत कानून द्वारा शासित एक बेटेहीन मालिक की बिना आवश्यकता के पैतृक भूमि को अलग करने की शक्ति का संबंध है, तो अब यह नियम अच्छी तरह से तय हो गया है कि यह उसके लिए खुला है, बशर्ते बिक्री निश्चित रूप से अनैतिक उद्देश्य के लिए न हो। प्रथागत कानून पर टॉपर की पुस्तक, 1879 संस्करण, प्रश्न संख्या 27 और जब इसका अनुवाद किया जाता है, तो इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

> *प्रश्न।* क्या प्रत्यावर्तनकर्ता एक पुत्रहीन मालिक द्वारा की गई पैतृक या गैर-पैतृक संपत्ति के अलगाव पर आपत्ति कर सकते हैं?
>
> *हल।* अलगाव पर आपत्ति नहीं की जा सकती। हालांकि, इसे चुनौती दी जा सकती है, और पूर्व-अनुभव के अधिकार को

मान्यता दी जाती है।

उपरोक्त प्रश्न और उत्तर के आधार पर, लाहौर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा *काला और अन्य* बनाम *माम चंद और अन्य,* (4) में कहा गया था कि रोहतक तहसील के एक बेबेटे मालिक के पास पैतृक संपत्ति पर अलगाव की व्यापक शक्तियां थीं। *सूबे सिंह और अन्य* बनाम *कन्हैया और अन्य* (5) मामले में, यह निर्धारित किया गया था कि रोहतक जिले की झज्जर तहसील में एक जाट के पास कृषि भूमि है। पुनजाब के पास इसे विचार के लिए स्थानांतरित करने की शक्ति थी और इस तरह के हस्तांतरण को उनके बेटे या अन्य प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी के कहने पर अलग नहीं किया जा सकता था जब तक कि बिक्री अनैतिक उद्देश्यों के लिए न हो। अजनबियों को उपहार देने से संबंधित रिवाज प्रश्न संख्या 102 में वर्णित है और इसका उत्तर 1910 में ई. जोसेफ द्वारा संकलित रोहतक जिले के प्रथागत कानून में दिया गया है। प्रश्न और उत्तर निम्नानुसार हैं:

प्रश्न: 'एक मालिक को अपनी संपत्ति, चल या अचल, पैतृक या अर्जित, को उन व्यक्तियों को उपहार देने की शक्ति दी गई है जो उससे संबंधित नहीं हैं, या दान में हैं। क्या बेटों की सहमति, यदि ऐसा हो या निकट संबंधियों की सहमति आवश्यक है? यदि निकट संबंधियों में से हैं, तो किसे ऐसा माना जाता है? (1) बेटों की अनुपस्थिति, (2) संपत्ति के विभाजित होने की परिस्थितियां, मालिक की ऐसे उपहार बनाने की शक्ति को कैसे प्रभावित करती हैं?

हल/ गुरियानी जैल और शेखों के बाहर झज्जर के पठान जवाब देते हैं कि एक आदमी अपनी किसी भी या सभी संपत्ति, संयुक्त या विभाजित, इच्छा से या दान में, किसी भी व्यक्ति को अपने उत्तराधिकारियों द्वारा

अनुमति या बाधा के बिना दे सकता है।

अन्य सभी जनजातियों का कहना है कि चल संपत्ति के उपहार में कोई प्रतिबंध नहीं है; अचल, स्व-अर्जित या पैतृक के रूप में, वह अपने उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना *दान में 25* बिस्वा की *दोहली* दे सकता है - यह या तो संयुक्त या विभाजित संपत्ति का हो सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि प्रश्न में या उसके उत्तर में कोई उल्लेख नहीं है / सेवाओं के बदले उपहार वैध था या नहीं। न ही इस संकलन में निहित किसी अन्य प्रश्न या उत्तर द्वारा कवर की गई सेवाओं के बदले उपहार है। ऐसा होने के कारण, हमें इस मुद्दे पर राज्य में प्रचलित सामान्य प्रथा पर वापस आना होगा। रैटिगन के डाइजेस्ट ऑफ ट्रेडिमेंटरी लॉ, 14 वें संस्करण, पैराग्राफ 59, अपवाद 3 में, यह उल्लेख किया गया है कि पैतृक अचल संपत्ति % आमतौर पर अहस्तांतरणीय है, लेकिन यह सिद्धांत निम्नलिखित अपवाद के अधीन है: -

"किसके और पराए के बीच संबंधों के पक्ष में अलगाव कुछ 'विशेष संबंध है, जैसे कि उनके द्वारा पालन-पोषण किया जाना या उनके साथ जुड़े होने के कारण या खेती में उनकी सहायता करने या भूमि के प्रबंधन में उनकी सहायता करने से जब वह खुद ऐसा करने में असमर्थ था। वे आम तौर पर रिवाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सेवाओं के बदले घनिष्ठ संबंध के पक्ष में एक उपहार दिया जा सकता है।

(नौ)अब मैं इच्छा के प्रश्न पर आ सकता हूं। इस बिंदु पर प्रथागत कानून के सिद्धांत को प्रश्न संख्या 93-ए में अभिव्यक्त किया गया है और इसका उत्तर ई. जोसेफ द्वारा संकलित प्रथागत कानून में दिया

गया है, जो इस प्रकार है: -

> जाट, अहीर, झज्जर के हिंदू राजपूत, ब्राह्मण और गुरियानी *जैल* के पठानों के पास वसीयत बनाने की कोई प्रथा नहीं है और कहते हैं कि, अगर कोई इसे बनाता है तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। गोहाना के पठानों और गोहाना और रोहतक के हिंदू और मुहम्मदराजपूतों का कहना है कि वसीयत लिखित में होनी चाहिए और उसका अनुपालन किया जाना चाहिए, लेकिन पैतृक संपत्ति की विरासत के मान्यता प्राप्त नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरियानी *जैल* के बाहर झज्जर के पठानों और झज्जर के शेखों का कहना है कि एक आदमी मौखिक या लिखित रूप से वसीयत बना सकता है, अपनी संपत्ति के एक तिहाई हिस्से, चल या अचल, पैतृक या अधिग्रहित, लेकिन अधिक के साथ नहीं। पठानों या राजपूतों द्वारा वसीयत का कोई उदाहरण पेश नहीं किया गया है, सिवाय गोहाना के राजपूतनी मुसुनीमत धन्ना द्वारा फौजदार खान के बेटे अल्लाह दाद के पक्ष में, और इसका कभी ऑपरेशन नहीं किया गया था।

प्रथम दृष्टया व्यक्त की गई राय पैतृक संपत्ति पर एक मालिक की वसीयत बनाने की शक्ति के खिलाफ है, लेकिन यहां फिर से प्रश्न में या उत्तर में कोई उल्लेख नहीं है कि क्या सेवाओं के बदले वसीयत बनाई जा सकती है। या नहीं। यदि अलगाव के तरीके के रूप में एक वसीयत को उपहार के साथ बराबर किया जा सकता है, तो यह मानना उचित होगा कि सेवाओं के बदले में एक वसीयत बनाई जा सकती है, ऊपर निकाले गए रैटिगन डाइजेस्ट के पैराग्राफ 59 के तीसरे अपवाद के आधार पर। *माली के मामले* (सुप्रा) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

पीठ ने कहा, 'दूसरी बात पर आते हुए, हमें ऐसा लगता है कि जहां तक पैतृक भूमि के अंतिम पुरुष धारक द्वारा किए गए अलगाव को चुनौती देने के महिला के अधिकार का सवाल है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह सच है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत एक बेटी उत्तराधिकारी है यदि एक पुरुष हिंदू की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है कि "कोई भी हिंदू वसीयत या अन्य वसीयत नामा द्वारा किसी भी संपत्ति का निपटान कर सकता है, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा निपटाए जाने में सक्षम है और हिंदुओं पर लागू है"। पंजाब प्रथागत कानून धारा 30 के अर्थ के भीतर कुछ समय के लिए लागू कानून है और वसीयतकर्ता चंदगी राम पर लागू था। रोहतक जिले में जाटों पर लागू पंजाब प्रथागत कानून के तहत चंदगी राम अनैतिक उद्देश्यों को छोड़कर अपनी संपत्ति को अलग कर सकते थे। *अब्दुल रफी खान* बनाम *लक्ष्मी चंद* (6) मामले में लाहौर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि "रोहतक जिले की गोहाना तहसील के एक पुरुष मालिक द्वारा पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि यह अनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बनाई जाती है। रैटिगन पैरा 56 बी में कहते हैं कि "प्रथागत कानून संपत्ति के मौखिक या लिखित हस्तांतरण करने की शक्ति के बीच अंतर को मान्यता देता है, न ही जहां हस्तांतरण की अप्रतिबंधित शक्ति मौजूद है, हस्तांतरण *अंतर* और हस्तांतरणकर्ता की मृत्यु पर प्रभावी होने के बीच। अलगाव के रूप को महत्वहीन माना जाता है।

(दस) जैसा कि पहले देखा गया है, "रोहतक तहसील में एक बेबेटे मालिक की अपनी पैतृक संपत्ति को विचार के लिए अलग करने की

शक्ति को तब भी मान्यता दी जाती है जब बिक्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते कि अलगाव (अनैतिक उद्देश्य) के लिए न हो। अलगाव के लिए विचार या तो नकद में किया जा सकता है या, एक प्रकार से, यानी सेवाओं के रूप में और यदि हस्तांतरण के बीच कोई अंतर नहीं है और एक हस्तांतरण जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित हस्तांतरणकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होता है, तो यह अनुमान लगाना उचित होगा कि सेवाओं के बदले घनिष्ठ संबंध के पक्ष में पैतृक भूमि के वसीयतनामा को निम्नानुसार मान्यता दी गई है। प्रथागत कानून। दोहराव की कीमत पर, मैं उस प्रश्न संख्या 12का उल्लेख करना चाहूंगा। [93-ए और उसके उत्तर में सेवाओं के बदले पैतृक संपत्ति के वसीयतनामा के मामले को स्पष्ट रूप से कवर नहीं किया गया है।

(ग्यारह) हाल ही में, ए एस बैंस, जे. को श्रीमती छोटा वी में इसी तरह के प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला / *दरयाओ सिंह और एक अन्य* (6 ए)। उस मामले में, एक ब्राह्मण के अपनी संपत्ति को वसीयत से निपटाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था। मैं इस दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूं।

पहले के एक मामले में, *भजना* वी। *मिहान आदि।* (7), ए. डी. कोशल, जे. (जैसा कि उस समय उनका प्रभुत्व था) ने निर्धारित किया कि एक भू-स्वामी अपने बेटों के बहिष्करण के लिए वसीयत बनाकर अपनी पैतृक भूमि को अलग नहीं कर सकता है। तब भी विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"यह मामला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने पैतृक स्वामित्व के एक हिस्से को अपने निकट संबंधियों के पक्ष में देने के मामले में एक बेटाहीन मालिक, जिसने उसे सेवाएं दी थीं, बेटों वाले मालिक से पूरी तरह से अलग है । इस संबंध में, बूटा सिंह और *निहाल सिंह*

बनाम भारत का संदर्भ उपयोगी हो *सकता* है। *उत्तम सिंह,* (8)।

(बारह) जैसा कि पहले देखा गया था कि धारी राम प्रॉपसिटस, जिनकी वसीयत पर इस मामले में सवाल उठाए जा रहे हैं, भी बेसुथरे थे। इस प्रकार, एक तरह से ए. डी. कोशल, जे. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी मेरे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

(तेरह) इसलिए, मैं पुष्टि में प्रश्न का उत्तर दूंगा और इसके परिणामस्वरूप अपील की अनुमति देता हूं और नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निर्णयों और डिक्री को रद्द करता हूं और वाद को खारिज करता हूं। हालांकि, पार्टियों को अपनी लागत ोंं को वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

दक्षिणी। *एस संधावालिया, सीजे-मैं* सहमत हूं।

गोकल चंद मित्तल, जे-मैं भी सहमत हूं।

1. आर.एस.ए. 889/72, 7 नवंबर, 1974 को तय किया गया।
2. 1979 आर.एल.आर. 361.
3. एस.सी. खंड II, 1970, पृष्ठ 395 के अप्रकाशित निर्णय।
4. ए.आई.आर. 1924 लाहौर 102.
5. 1964 (2) एससी रिपोर्ट 899।
6. आई.एल.आर (1935) 16 लाह 505।
7. आर.एस.ए. 466/72, 1 मई, 1978 को तय किया गया।
8. 1972 सी.एल.जे.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy